पत्रिका, 5 मार्च 2021

सीएजी ने जताई आपत्ति

14470 करोड़ के खर्चे का हिसाब नहीं दिया विभागों ने

भोपाल. राज्य के 25 विभागों ने सहायता अनुदान से संबंधित 14470.62 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत नहीं किए। इस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने से राशि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने गुरुवार को यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। रिपोर्ट में सरकार के बजट और खर्च का ब्यौरा है। इसमें नियम विरुद्ध खर्चों और बजट में अनावश्यक राशि लिए जाने पर भी ऐतराज जताया गया है।